

My Notes.....

राष्ट्रीय

आर्थिक आधार पर आरक्षण का बचाव

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के फैसले का बचाव किया है। केंद्र ने कहा है कि आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गए लोगों को समान अवसर मुहैया कराकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। सरकार ने कहा कि नया कानून 1992 के इंद्रा साहनी बनाम केंद्र (मंडल आयोग फैसले के नाम से ज्ञात) के दायरे में नहीं आता है। इसका कारण यह है कि आरक्षण के लिए प्रावधान संविधान संशोधन के बाद किया गया है।

क्या है

1. केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है, 'संविधान संशोधन (103वां) अधिनियम 2019 समाज में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को लाभ देने के लिए आवश्यक था। ये लोग आरक्षण के उपलब्ध दायरे में नहीं आते थे। सांख्यिकी के अनुसार भारतीय जनसंख्या में ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं।'
2. केंद्र ने कहा है कि समाज के सभी कमजोर वर्ग को न्याय मुहैया कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन आवश्यक था। सरकार को समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित विभिन्न न लाभ देने के लिए समर्थ बनाना जरूरी था। समाज के ऐसे लोग मौजूद आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे।
3. केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन (103वां) अधिनियम 2019 के खिलाफ दायर कई याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दायर किया है।
4. याचिकाओं में संशोधन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह इंद्रा साहनी बनाम केंद्र मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है और यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।

200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी

13 पॉइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर देशभर में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर को अनुमति दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया ताकि रिजर्व कैटिगरी के एससी, एसटी और ओबीसी को विश्वविद्यालय फौकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। पॉइंट रोस्टर को लेकर विवाद चल रहा था। देश भर में इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए और 5 मार्च को विभिन्न न संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इंकार इन्कार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था। 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध होते देखकर सरकार ने 200 पॉइंट रोस्टर लाने के संकेत पहले ही दे दिए थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एनडीए में सहयोगी एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने भी 13 पॉइंट रोस्टर फैसले को बदलकर अध्यादेश के जरिए 200 पॉइंट रोस्टर लाने की बात की थी।

क्या है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली

1. 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए विभाग के आधार पर आरक्षण लिस्ट तैयार होगी। इसके तहत नियुक्तियां विभागानुसार होनी थी, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे थे।
2. विरोध की वजह है कि विभागानुसार नियुक्ति के कारण आरक्षित वर्ग के लिए सीटों की संख्या पर असर पड़ता। यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए बहुत कम सीटें निकलती हैं और ऐसे में विभागानुसार रोस्टर होने पर आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो जातीं।

3. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी के बदले विभागानुसार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था।
4. केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। सर्वोच्च अदालत ने इसमें बदलाव से इंकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ही प्रभावी रहेगा।

कच्छ में मिले हड़प्पा युग के कंकाल और खजाना

गुजरात के कच्छ जिले में दो महीनों की खुदाई के बाद पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। धौलावीरा से लगभग 360 किलोमीटर दूर इस स्थान पर 250 से ज्यादा कब्रें हैं जो लगभग 5 हजार साल पुरानी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इस संभावना को बल मिलता है कि किसी समय में यहां मनुष्यों की अच्छी-खासी आबादी निवास करती थी। कच्छ जिले के लखपत तालुका के खाटिया गांव में यह खुदाई कच्छ यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां मिली 250 से ज्यादा कब्रें 4 हजार छः सौ से 5 हजार दौ सौ साल पुरानी हैं। यह कब्रिस्तान 300मीटर x 300मीटर आकार का है। इनमें से अभी तक 26 कब्रों की खुदाई हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ी कब्र 6.9 मीटर की, जबकि सबसे छोटी 1.2 मीटर की है।

क्या है

1. पुरातत्वविदों को यहां एक कब्र से छह फुट लंबा एक मानव कंकाल मिला है, यह लगभग 5 हजार साल पुराना है। कच्छ यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के प्रमुख सुरेश भंडारी ने बताया, 'इस कंकाल को केरल यूनिवर्सिटी ले जाया गया है। यहां उसकी उम्र, लिंग और मृत्यु के संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा'।
2. पहली बार गुजरात में आयताकार कब्रिस्तान मिला है। इससे पहले मिलने वाले कब्रिस्तान गोलाकार या अर्द्धगोलाकार आकार के थे। इन कब्रों में मानव कंकाल के अतिरिक्त बच्चों की कब्रें और जानवरों के अवशेष मिले हैं। खुदाई में सीपी के बने कंगन, पत्थर की चक्कियां, पत्थर के ब्लेड भी मिले हैं।
3. कब्रों में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, एक कब्र में अधिकतम 19 और कम से कम 3 बर्तन शव के पैरों के पास रखे थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि ऐसे बर्तन पाकिस्तान के आमरी, नाल और कोट से भी बरामद हुए हैं। भारत में उत्तरी गुजरात में ये नागवाडा, छतराद सहेली, मोटी पीपली और कच्छ में सुरकोतड़ा और धानेती से मिले हैं।
4. सुरेश भंडारी का कहना था, 'खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों, पत्थरों के ढेर और दूसरी चीजों के भूरासायनिक परीक्षण से हमें पता चलेगा कि इन्हें उस समय के लोगों ने किस तकनीक से बनाया, इन्हें बनाने में कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया था। तमाम प्रयोगशालाओं में जांच के बाद हमें खाटिया के पास रहने वाले प्रारंभिक हड़प्पा युग के निवासियों के इतिहास की जानकारी मिलेगी'।

फलैशबैक

1. सिंधु घाटी सभ्यता (3300 ईसापूर्व से 1700 ईसापूर्व तक, परिपक्व काल 2600 ई.पू. से 1900 ई.पू.) विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है।
2. जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है।
3. प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ, यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के तीन शुरुआती कालक्रमों में से एक थी, और इन तीन में से, सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित।
4. सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और 'सिंधु-सरस्वती सभ्यता' के नाम से भी जानी जाती है।

भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम की पहली कार्यशाला

नीति आयोग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) ने भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम (आईईएमएफ) की पहली कार्यशाला आयोजित की। यह फोरम भारत ऊर्जा भविष्य के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान, परिदृश्य, परिचर्चा व योजना निर्माण के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लैबोरेटरी (पीएनएनएल) के सहयोग से इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के उद्घाटन उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार तथा यूएसएआईडी इंडिया के मिशन डायरेक्टर श्री मार्क ए व्हाइट ने संयुक्त द्रव्य रूप से की।

क्या है

1. आईईएमएफ, विशेषज्ञों व नीति निर्माताओं को ऊर्जा तथा पर्यावरण के मुद्दों पर विचार करने का एक मंच है। फोरम का लक्ष्य भारत सरकार तथा नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाना है। फोरम ने भारतीय संस्थानों के क्षमता निर्माण और शोध के लिए भविष्य के क्षेत्र की पहचान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
2. कार्यशाला में आठ विशेषज्ञ-सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में भारत-केन्द्रित ऊर्जा प्रारूपण पर चर्चा हुई।
3. सत्र में इस विषय पर भी परिचर्चा हुई कि भारत के ऊर्जा प्रारूपण और विश्व के ऊर्जा प्रारूपण, किस प्रकार नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? पैनल विशेषज्ञों ने ग्रामीण-शहरी विभेद को कम करने पर विशेष जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि व्यावहारिक ऊर्जा मॉडल के लिए ऊर्जा खपत और स्थानीय स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. भारत-केन्द्रित मॉडल में भारत के नगरों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए। भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए विद्युत आधारित परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों तथा पर्यावरण की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
5. केन्द्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा उत्पादन और खपत के संदर्भ में सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक लागत पर विशेष बल दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य के ऊर्जा संबंधी नीति-निर्माण के लिए इन लागतों का सटीक आंकलन किया जाना चाहिए।
6. कार्यशाला में आवास और शहरी मामले मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पीओएसओसीओ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण; अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यूरोपीय संघ, जीआईजेड, डीएफआईडी, ईडीएफ; भारतीय शोध संस्थान (सीईईडब्ल्यू, टीईआरआई, सीएसटीईपी, आईआरएडी, प्रयास, आईआईएम अहमदाबाद, एनआईटी भोपाल आदि) के प्रतिनिधियों व ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड वीडियो वॉल का उद्घाटन

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री हरदीप एस पुरी ने कहा है कि शहरों के डेटा स्मार्ट समाधानों को लागू करने की प्रक्रिया के शुभारंभ के साथ ही शहरी परिवर्तन की दिशा में डेटा एक महत्वपूर्ण त्वपूर्ण परिसंपत्ति और डेटा संचालित शासन में सक्षम हो जाता है। अत्याधुनिक इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह शहरों में वास्तविक समय और अभिलेखीय स्रोतों दोनों से असंख्य स्रोतों के माध्यम से डेटा प्राप्त करेगा। वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय के विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नागरिकों/आगंतुकों के साथ निरंतर सक्रिय जुड़ाव के उद्देश्य से ऑब्जर्वेटरी और विभिन्न अभियानों/कार्यालयों से प्राप्त अनुभवों का प्रदर्शन करेगी।

क्या है

1. इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री हरदीप पुरी ने कहा कि समुदायों के सशक्तीकरण के लिए यह जरूरी है कि शहर अपनी कार्यप्रणाली, सार्वजनिक सेवाओं, शासन प्रणालियों, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्धियों और विफलताओं को

- सुधारने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करें और सूचना तक पहुंच के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करें।
2. **शासन का भविष्य डेटा-संचालित है** और भारतीय शहर अपने कामकाज में इस बदलाव को अपनाने लगे हैं। लोगों को इस दिशा में केन्द्रित करने के लिए शासन में परिणाम आधारित योजना की ओर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।
 3. ऑब्जर्वेटरी से परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल, वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए सार्थक संकेतकों की विश्वसनीय जानकारी को अद्यतन करने में मदद मिलेगी। इससे सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और भविष्य की रणनीतियों को आवश्यकता अनुरूप और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विकसित करने में भी सहायता मिलेगी।
 4. ऑब्जर्वेटरी की संकल्पना 'चतुर्भुज हेलिक्स'- मॉडल के सभी चार हितधारकों- सरकार, नागरिक, शिक्षा और उद्योग के साथ-साथ शहरी निकायों की निर्णय प्रक्रिया और उनके आंतरिक कार्यों के बीच जुड़ाव को बढ़ाने के लिए इनके मूल्य को पहचानती है।
 5. इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी भविष्य में मंत्रालय का प्रमुख डेटा विश्लेषण और प्रबंधन केंद्र केन्द्र बन जाएगा। इससे अत्याधुनिक तकनीकों और सहयोगों के उपयोग के माध्यम से शहरीकरण के लिए जटिल चुनौतियों हेतु वैज्ञानिक प्रतिक्रिया और समाधान भी प्रदान किए जाएंगे।
 6. इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी जटिल शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए हाल ही में शुभारंभ की गई डेटा स्मार्ट शहर रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो शहरों में इन चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग हेतु डेटा का संग्रह बनाता है।
 7. इस रणनीति का मूल उद्देश्य तीन आधारभूत स्तंभों पीपुल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म की आधारशिला रखना है और शहरों में डेटा के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के साथ सुधार हेतु सुझाव देना है।
 8. शहरों को डेटास्मार्ट बनाने के लिए शहरों में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और नवाचार पारिस्थितिकी प्रणालियों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

वेब वंडर वुमेन

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों उपलब्धियों को मानने मनाने के लिए आयोजित अभियान वेब वंडर वुमेन का अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के बाद 30 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें नई दिल्ली से महिला में मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रीमती मेनका संजय गांधी ने सम्मानित किया।

क्या है

1. ट्विटर इंडिया तथा बग ब्रेकथू इंडिया के सहयोग से आयोजित इस समारोह का उद्देश्य विश्व की उन भारतीय महिला हस्तियों की दृढ़ता और साहस को मान्यता देना है जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सार्थक अभियान चलाने में सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है।
2. श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि वुमेन ऑनलाईन बहुत शक्तिशाली आवाज है। वेब वंडर वुमेन ऐसी आवाजों को मान्यता देने, सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए है, जिन्होंने अपनी क्षमता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सार्थक प्रभाव डाले हैं।
3. महिला मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 10 निर्णायकों के पैनल के साथ 30 महिलाओं के नामों को अंतिम रूप दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित किया है। इन महिलाओं का चयन 240 से अधिक नामांकनों से मीडिया, जागरूकता, कानूनी, स्वास्थ्य, सरकारी, खाद्य, पर्यावरण, विकास, व्यवसाय तथा कला श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त किए गए।
4. मंत्रालय 8 मार्च को उन महिलाओं को 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित करेगा, जिन्होंने समाज के प्रति योगदान दिया है लेकिन गुमनाम रहीं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा।

5. इन पुरस्कारों के साथ मंत्रालय ने उन महिलाओं को मान्यता देने की नई प्रणाली शुरू की है जिन्होंने सीमा रेखा पार करके असामान्य क्षेत्रों में काम किया है।
6. 2018 में मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल 'फस्ट लेडीज' प्रारंभ किया ताकि उन असाधारण महिलाओं को सम्मानित किया जा सके, जो अपने क्षेत्रों में मील का पत्थर स्थापित करने में प्रथम रही हैं।
7. मंत्रालय ने 2015 में '100 महिला अचीवर' को मान्यता देने के लिए फेसबुक के साथ सहयोग किया था, जिन्होंने विभिन्न न न सार्वजनिक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की। वेब वंडर वुमेन मंत्रालय का महिला अचीवरो का तीसरा अभियान है।

लोकतांत्रिक शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ा : रिसर्च

लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करती हैं जबकि राजशाही या तानाशाही शासन में ऐसी बात नजर नहीं आती। अमेरिका के एमआईटी के एक अध्ययन में यह बात सामने आई, जिसके लिए 184 देशों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन पॉलिटिकल इकॉनमी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

क्या है

1. इसमें यह भी पाया गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले देशों में पहले के राजशाही शासन की तुलना में 25 साल की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
2. शोधकर्ताओं ने पाया कि लोकतंत्र में व्यापक आधार पर विशेषकर स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है जो राजशाही या निरंकुश शासन व्यवस्था में कम नजर आती है।
3. अमेरिका में मैसाचुसट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (एमआईटी) से डेरॉन एसमोगलू ने कहा, 'लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने वाले कई तरह के सुधार विशेष तरजीह से मुक्त होते हैं। यानी यहां सभी के लिये समान व्यवस्था होती है जबकि गैर-लोकतांत्रिक शासन में अपने कृपापात्रों को विशेष तरजीह देने की प्रवृत्ति देखी गयी है।'
4. एसमोगलू ने एक बयान में कहा, 'लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अपने धन का इस्तेमाल कई कामों में किया, लेकिन जिन दो क्षेत्रों को इससे मजबूती मिली वह स्वास्थ्य और शिक्षा हैं।' शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिये 184 देशों से प्राप्त 1960 से 2010 के दौरान के आंकड़ों का अध्ययन किया।

एटीजीएम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण

पाकिस्तानी टैंकों को आसानी से टारगेट करने के लिए भारत ने नई मिसाइल बनाई है। 13 मार्च 2019 की रात को डीआरडीओ (The Defence Research and Development Organisation) द्वारा विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया। इन्फेन्ट्री के लिए विकसित की गई इस मिसाइल से सेना को काफी मदद मिलेगी। इसकी मांग सेना लंबे समय से कर रही है। 2 से-3 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज के साथ इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत पाकिस्तान से लगभग 15 हजार किलोमीटर की जमीनी सीमा शेयर करता है। भारतीय सेना को जमीन पर काफी मजबूती मिलेगी। 2021 से इसके मास प्रोडक्शन की संभावना है। 2.5 किमी रेंज वाली इस मिसाइल का निर्माण भारत में होगा। इसकी तुलना अमेरिका में बनी एफजीएम-148 से हो रही है। भारत ने इसे एफजीएम-148 को दरकिनार करके चुना था।

क्यों खास है ये मिसाइल

1. यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।

भारत को होंगे ये फायदे

1. पाकिस्तान और चीन के मुकाबले संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।
2. युद्ध में जमीनी सेना को मजबूती मिलेगी।
3. सेना को इसके ट्रांसपोटेशन में आसानी होगी।

2. यह एक **मैन पोर्टेबल मिसाइल** है। इसे आसनी से ले जाया जा सकता है।
3. इसे **टैंक और हेलिकॉप्टर या लड़ाकू विमान से भी इस्तेमाल** किया जा सकता है।
4. इसे कंधे पर रखकर भी दागा जा सकता है।

अल नागाह 2019

भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यासों की शृंखला में तीसरा अल नागाह III अभ्यास 12 से 15 मार्च 2019 तक ओमान की जबल अल अखदर पहाड़ियों पहाड़ियों में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अर्द्ध शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों कार्रवाइयों में पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ युद्धकौशलों, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान ख प्रदान करेंगी।

क्या है

1. भारत-ओमान के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध 2006 में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की बैठकों के बाद से निरंतर विकसित हो रहे हैं।
2. अभ्यास अल नागाह III से पहले दो संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। जिनका आयोजन क्रमशः ओमान में जनवरी 2015 तथा भारत में मार्च 2017 में किया गया था।
3. इस प्रकार, हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के दोनों महत्वपूर्ण देशों के बीच बढ़ती सैन्य तथा सामरिक साझेदारी पर बल देते हुए इसी तरह के अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं और वायु सेनाओं के बीच भी प्रचलन में हैं।
4. भारतीय सेना के दस्ते का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन के 4 अधिकारियों, 9 जूनियर कमिश्नड अधिकारियों और 47 अन्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा।
5. रॉयल आर्मी आफ ओमान (आरएओ) की जबल रेजीमेंट की ओर से भी इतने ही सैन्य कर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
6. पर्यवेक्षक शिष्टमंडल में दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो 25 मार्च, 2019 को इस अभ्यास के समापन के गवाह बनेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच उनकी क्षमताओं की समझ को बढ़ाने तथा मैत्री को मजबूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

डीजीपी नियुक्ति मामला मे सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का DGP नियुक्ति पर फैसला आया है। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट को कम से कम छह महीने का वक्त क्त बचा हो यूपीएससी उन्हीं को नियुक्ति पैनल में शामिल करने पर विचार करेगा। जिनकी सेवानिवृत्ति त्रति को छह महीने से कम वक्त ख्त बचा है उनके नाम पर विचार नहीं होगा। बता दें कि डीजीपी का दो साल का निश्चित कार्यकाल होता है। राज्य सरकारें जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति सत्रति होने वाली होती थी उन्हें डीजीपी नियुक्त कर देती थी और उन्हें दो साल का निश्चित कार्यकाल मिल जाता था।

क्या है

1. गौरतलब है कि साल 2006 में पुलिस सुधार पर दिए गए आदेश को लागू न करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर 2006 में पुलिस सुधार को लेकर आदेश दिए थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होगा।
3. अवमानना याचिका में आरोप है कि साल 2006 में पुलिस सुधार पर दिए गए अदालत के आदेश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक लागू नहीं किया। याचिका में इन राज्यों पर अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग की गई है।

4. वही पहले भी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और सभी राज्यों को एक्टिंग डीजीपी नियुक्त नहीं करने के लिए आदेश दे चुका है। कोर्ट ने कहा था कि ये कदम उठाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
5. पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकारें डीजीपी या पुलिस कमिश्नर पद पर आसीन अधिकारी के रिटायरमेंट से तीन महीने पहले दावेदार पुलिस अधिकारियों के नाम यूपीएससी के पास भेजें।
6. इन नामों में से तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी बनाएगी और इन नामों में से किसी भी एक को डीजीपी चुनने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र रहेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगर राज्य सरकार का अलग से कोई कानून है तो उस पर रोक लगेगी। होगी।

अभ्यास संप्रति-2019 का समापन

भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति **VIII**, 14 मार्च, 2019 को तंगेल, बांग्लादेश में संपन्न न हुआ। भारत-बांग्लादेश संयुक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स की 9वीं बटालियन का कंपनी ग्रुप तथा 36वीं ईस्ट बंगाल बटालियन बांग्लादेश की कंपनी ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय उच्चायुक्त महामहिम श्रीमती रीवा गांगुली दास ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों पर प्रकाश डाला।

क्या है

1. संयुक्त अभ्यास की संप्रति शृंखला, 2009 में प्रारंभ हुई थी और यह 8वां अभ्यास था। संप्रति अभ्यास भारत तथा बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतरसंचालन और सहयोग को मजबूत और व्यापक बनाता है।
2. तंगेल, बांग्लादेश में यह चौथा भारत-बांग्लादेश अभ्यास था। दोनों देशों के कमांडरों और स्टाफ अफसरों ने गुप्तचर सूचना प्राप्ति और सूचना साझा करने और संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण घटकों को उचित संचालन आदेश जारी करने में आपसी सहयोग के साथ कार्य किया।
3. संयुक्त प्रशिक्षण में तंगेल के बंगबंधु सेनानिवास छावनी में वैलिडेशन अभ्यास किया गया जिसमें दोनों देशों की सेनाओं की उप इकाइयों ने योजनाओं को अंजाम दिया। इस अभ्यास की समीक्षा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई।
4. प्रशिक्षण के अतिरिक्त दोनों दस्तों ने मैत्री बॉलीवॉल एवं बास्केटबॉल मैच सहित अनेक गतिविधियों में भागीदारी की। भारत-बांग्लादेश के संयुक्त अभ्यास के सफल समापन के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन किया गया और रस्मी स्मृति चिन्हों का आदान-प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (ए) - ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता (बी) - ट्रेडमार्क के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता (सी) - औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए लोकार्नो समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

क्या है

1. नाइस, वियना और लोकार्नो समझौतों में पहुंच स्थापित करने से वैश्विक रूप से अपनाई जा रही वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार ट्रेड मार्क और डिजाइन अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों से तालमेल के लिए भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालय को मदद मिलेगी।
2. यह भारतीय डिजाइनों, प्रतीकात्मक तत्वों और वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करेगा।

3. इस पहुंच से भारत में आईपी के संरक्षण के संबंध में विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने की उम्मीद है। इस पहुंच से समझौते के तहत वर्गीकरणों की समीक्षा और संशोधन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकारों का उपयोग करने में भी आसानी होगी।

OIC बैठक में भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच 1 मार्च 2019 को विदेश मंत्रालय, महिला मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज अबू धाबी में 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) को संबोधित किया। OIC के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान जोकि की इसका संस्थापक सदस्य भी है, इस बैठक में नहीं था। भारत को न्योता मिलने से घबराए बौखलाए पाक ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। पाक की तमाम कोशिशों के बाद भी OIC ने भारत को भेजा न्योता रद्द नहीं किया।

क्या है

1. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत न तो OIC का सदस्य है और न ही उसे संगठन ने पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया है। इसके बाद भी OIC की तरफ से भारत को न्योता देना पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है।
2. पाकिस्तान ने OIC को भारत को दिए न्योते को रद्द करने की मांग की थी लेकिन उसकी मांग को कोई तवज्जो नहीं मिली। इससे घबराए बौखलाए पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार किया है। इस तरह यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है।
3. पाकिस्तान के लिए यह तगड़ा झटका इसलिए भी है कि वह हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है और इस संगठन में भारत की एंट्री का विरोध करता आया है। थाइलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को भी OIC के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है लेकिन 18.5 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत को यह दर्जा नहीं है।
4. पाकिस्तान इससे पहले भी एक बार भारत को न्योता दिए जाने का विरोध किया था और तब OIC उसकी मांग के आगे झुक गया था। इस बार खुद की मांग को भाव नहीं मिलने से पाकिस्तान का विरोध जारी करना सही है। बौखलाना लाजिमी है।
5. 50 साल पहले 1969 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सऊदी अरब की सलाह पर OIC के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया गया था।
6. हालांकि पाकिस्तान की आपत्ति के बाद OIC ने आखिरी वक्त में भारत को दिया न्योता रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बीच रास्ते से लौटना पड़ा था।
7. भारत के OIC के ज्यादातर सदस्य देशों खासकर पश्चिम एशियाई देशों से अच्छे संबंध हैं। यूएई के साथ तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं।
8. कतर ने 2002 में पहली बार भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया था। तुर्की और बांग्लादेश तो भारत को OIC सदस्य बनाए जाने की मांग कर चुके हैं।

क्या है OIC

1. आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) मुस्लिम देशों का संगठन है।
2. चार महादेशों में 57 देश इसके सदस्य हैं। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है।
3. 25 सितंबर, 1969 को मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में इस संगठन के स्थापना का फैसला किया गया था।
4. इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दाह में है। इसके मौजूदा महासचिव युसूफ बिन अहमद अल उसैमीन हैं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (आईसीएफएम) की 1970 में पहली मीटिंग हुई।

9. इस बार भारत तो न्योता देने वाले UAE की आबादी में एक तिहाई भारतीय हैं। उसने भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी निवेश किया है। इसके अलावा, UAE भारत के अनुरोध पर राजीव सक्सेना और क्रिस्चन मिशेल जैसे आरोपियों का प्रत्यर्पण कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी सहयोग किया है।

दूसरी बार ब्रेजिट करार खारिज

ब्रिटेन की संसद ने 12 मार्च 2019 देर रात प्रधानमंत्री टेरीजा मे के ब्रेजिट करार को दूसरी बार खारिज कर दिया। इससे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की तय तारीख से दो हफ्ते पहले देश अनिश्चितता के दौर में चला गया है। ब्रिटिश संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमंस' 8 शहाउस ऑफ कॉमंस ने 242 के मुकाबले 391 वोटों से इस करार को खारिज कर दिया। इससे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने ब्रेजिट समझौते पर अपनी कन्जर्वेटिव पार्टी के सांसदों से अपील की थी कि वे अपनी 'निजी प्राथमिकताओं' को दरकिनार कर इस समझौते पर एकजुट हों।

क्या है

1. ब्रिटेन को 29 मार्च को 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ से अलग होना है लेकिन टेरीजा मे के ब्रेजिट इस संबंधी समझौते को लेकर संसद में समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
2. टेरीजा मे के ब्रेजिट ने पिछले महीने अपनी पार्टी के सभी 317 सांसदों को पत्र लिखकर अपील की थी कि वे 'निजी प्राथमिकताओं' को अलग दरकिनार करें। उन्होंने चेताया था कि यदि ब्रिटेन बिना किसी समझौते के ईयू से बाहर निकलता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था और आमजन के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। इससे देश और यूरोपीय संघ में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
3. गौरतलब है कि ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' ने जनवरी में भी समझौते को खारिज कर दिया था और इसमें ठोस बदलाव न होने की स्थिति में इसके मंगलवार को भी ऐसा ही करने की आशंका थी।
4. टेरीजा मे के ब्रेजिट की इस हार के बाद ब्रिटेन के सांसद 13 मार्च 2019 को वोट देंगे कि बिना समझौते के 29 मार्च को ईयू को छोड़ा जाए अथवा नहीं।

जमात-ए-इस्लामी पर लगा प्रतिबंध

कश्मीर में एक अलगाववाद पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए जमात-ए-इस्लामी पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में यह कहा है कि जमात-ए-इस्लामी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो कि आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इसे एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है।

क्या है

1. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जमात-ए-इस्लामी के अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने की बात कही गई है।
2. इसके अलावा इसको नफरत फैलाने के इरादे से काम करने वाला एक संगठन भी बताया गया है, जिसके बाद मंत्रालय ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से संगठन को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। हाल ही में एजेंसियों ने कश्मीर घाटी से जमात-ए-इस्लामी के तमाम सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
3. घाटी में 22 फरवरी को हुई एक बड़ी कार्यवाही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात-ए-इस्लामी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं को घेराबंदी हिरासत में लिया था।
4. 22 फरवरी की रात दक्षिण, मध्य और उत्तरी कश्मीर के इलाकों में यह छापेमारी की गई थी, जिसमें जमात संगठन के प्रमुख अब्दुल हमिद फयाज सहित दर्जनों नेताओं को घेराबंदी हिरासत में लिया गया।
5. इस कार्रवाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की थी। इसके अलावा पूर्व राज्यमंत्री सज्जाद लोन ने इस कार्रवाई पर आपत्ति उठाई थी। सवालिया निशान लगाए थे।

कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 14 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत, ब्रिटेन कैंसर शोध पहल क्लिनिकल क्लिनिकल शोध, जनसांख्यिकी शोध, नई टेक्नोलॉजी और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के अग्रणी विशेषज्ञों को साथ लेकर लाकर क्लिफायती, रोकथाम तथा कैंसर देखभाल जैसी शोध चुनौतियों को पहचान करेगी। यह पहल नये शोध गठजोड़ विकसित करने में पहल करेगी और कैंसर परिणामों के विरुद्ध प्रगति को सक्षम बनाने में प्रभावी शोध कार्य करेगी।

क्या है

1. 5 वर्षों में इस पहल के लिए कुल शोध धनराशि कोष 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) का होगा।
2. इस कोष में कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) की हिस्सेदारी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की हिस्सेदारी भी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) की होगी। दोनों की बराबर निधियां वित्त वर्ष प्रारंभ होने के समय जारी दरों के अनुसार होंगी।
3. कैंसर परिणामों में सुधार के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल, क्लिनिकल क्लिनिकल तथा फार्मास्युटिकल नवाचारों में वृद्धि के बावजूद कैंसर देखभाल पर बढ़ते खर्च को पूरा करने में विश्व की चराचर स्वास्थ्य प्रणाली बोझ से दबी स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से सशक्त नहीं हो पाएगी। पापी लैस नहीं हो पाएगी।
4. भारत-यूके कैंसर शोध पहल ने श्रेष्ठ शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों तथा संस्थानों को एक-दूसरे से जुड़ने में सहयोग के लिए रूपरेखा तय की है, ताकि कैंसर देखभाल के लिए उच्च मूल्य और कम लागत के बहु-विषयक शोध मंच तैयार हो सके।
5. इस पहल के माध्यम से डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल स्तर के शोधकर्ताओं और प्रारंभिक कैरियर केरियर के वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे शोधकर्ता न केवल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें अकादमिक क्षेत्र और संबंधित बायो-फार्मा उद्योग में निश्चित अवधि के शोध कार्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि

1. भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध पहल विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) का 5 वर्ष का सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है।
2. यह कार्यक्रम कैंसर के क्लिफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। 5 वर्ष में सीआरयूके और जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों 5-5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) का निवेश करेंगे और संभावित धन देने वाले सहयोगियों से आगे निवेश की कोशिश करेंगे।
3. भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 18 अप्रैल, 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में की गई थी।
4. संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था कि “उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में हम घनिष्टता के साथ काम करने की इच्छा साझा करते हैं और उन सभी के साथ घनिष्टता के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो सहमत अंतर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों, वैश्विक शांति और स्थिरता मर्यादित करने वाली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समर्थन देने में हमारे उद्देश्यों को साझा करते हैं।
5. एक साथ भारत और ब्रिटेन एक अनिश्चित विश्व में अच्छाई के लिए एक शक्ति हैं। हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते हैं।
6. भारत का जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) की द्विपक्षीय शोध पहल लांच करने का प्रस्ताव करते हैं, जो कैंसर के इलाज के लिए कम लागत पर फोकस करेगी”।

भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी

भारत-अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन 17 से 19 मार्च, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ और एक्जिम बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया है। यह सम्मेलन भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को और गहरा बनाने के साथ-साथ सीमा पार की परियोजनाओं में संपूर्ण साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से इस वार्षिक सम्मेलन ने भारत और अफ्रीका के वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों, अधिकारियों, व्यवसायियों, व्यावसायिकों, बैंकरों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, स्टार्ट-अप उद्यमियों और अन्य पेशेवरों को साझेदारी साझेदारी की भावना से एक मंच पर लाने का काम किया है।

क्या है

- घाना गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉ. महामुदू बावूमिया, गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिमा कसोरी फोफाना, लेसोथो के उप-प्रधानमंत्री मोनियाने मोलेलेकी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे।
- सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सी.आर चौधरी तथा वाणिज्य विभाग में सचिव डॉ. अनुप वधावन भी शामिल होंगे। 36 देशों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों के अलावा 21 अफ्रीकी देशों से 31 से अधिक वरिष्ठ मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
- सम्मेलन 'उत्तरी दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के बीच उत्कृष्ट साझेदारी में योगदान देगा। सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बढ़ते संरक्षणवाद और व्यापार टकरावों के कारण उत्पन्न हो रही हैं।
- भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी साझेदारी भारत के तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रभुत्व कायम करने से संवर्धित हुई है। साथ ही सब सहारा की कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अफ्रीका की नई अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देखने को मिली है, जो दुनिया की 10 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- यह सम्मेलन भारत सरकार के अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव की विस्तृत संकल्पना के अनुकूल है। सरकार भारत-अफ्रीका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी से स्पष्ट है जो वर्ष 2017-18 में 62.66 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
- सम्मेलन के जानकारी सत्र में द्विपक्षीय, आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी के संभावित क्षेत्रों, भारतीय और अफ्रीकी उद्यमों की क्षमताओं तथा संयुक्त उद्यम के अवसरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

विचार-विमर्श के दौरान जिन दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विशेष रूप से चर्चा होगी वे हैं -

- अगले कुछ वर्षों में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 150 बिलियन तक पहुंचाना
- भारतीय निर्यातकों को अफ्रीकी देशों तक पहुंच स्थापित करने के लिए प्रोसाहित करना और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बढ़ाना
- अफ्रीका को भारत से निर्यात के लिए भौगोलिक और उत्पाद विविधता शुरू करना।
- भारत से शुल्क मुक्त सीमा शुल्क प्राथमिकता की योजना और क्षमता निर्माण सहायता के अधिकतम इस्तेमाल द्वारा अफ्रीका के निर्माण निर्यात को बढ़ावा देना।
- बुनियादी ढांचा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा सेवाओं, आईटी और ज्ञान उद्योगों जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश का विस्तार।
- उम्मीद है कि सम्मेलन में अफ्रीका के 400 से अधिक और भारत से 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में बी2बी बैठकों में अफ्रीका के 500 से अधिक परियोजना प्रस्तावों के भविष्य के बारे में चर्चा होने की भी उम्मीद है।

अर्थशास्त्र

पीएम-एसवाईएम योजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वारांगल वस्त्रल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच पीएम-एसवाईएम पेंशन कार्ड का वितरण भी किया। 3 लाख जन सेवा केंद्रों में 2 करोड़ श्रमिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम-एसवाईएम योजना को देश के असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3 हजार रुपये के मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब इस प्रकार की योजना की शुरुआत हुई है।

क्या है

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम-एसवाईएम योजना के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाभार्थी द्वारा योगदान में दी गई राशि के बराबर की राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
2. उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपये प्रति महीने से कम है वे निकट के जन सेवा केंद्रों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
3. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म जमा करना होता है और इसमें आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। जन सेवा केंद्र में पंजीकरण करने से संबंधित लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। यह डिजिटल इंडिया का जादू है।
4. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आसपास काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए सहायता प्रदान करें। उच्च आय वर्ग के लोगों के इस कार्य से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। श्रमिकों को सम्मान देने से राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
5. केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न न्य योजनाएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। जैसे- आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम आवास योजना, उज्वला योजना, सौभाग्य योजना, और स्वच्छ भारत मिशन आदि।
6. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धा वृद्धावस्था अवस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं जैसे- स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत, जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और शारीरिक अक्षमता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।

सीटीआई-2019

राजकोट, रांची, इंदौर, चेन्नई, अगरतला और लखनऊ लाइव प्रयोगशालाओं की सेवा के लिए प्रकाशस्तंभ परियोजनाओं के रूप में चिह्नित हत चिन्हित- जून 2019 के लिए लक्षित टीईसी द्वारा चयनित 25 देशों के 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी सीटीआई एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होगा निर्माण प्रौद्योगिकी भारत - 2019 - एक्सपो-सह-सम्मेलन - वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती और भारत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि सीटीआई-2019 में 32 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

क्या है

1. लाइटहाउस परियोजनाओं के लिए छह शहरों की पहचान की गई है, जो लाइव प्रयोगशालाओं प्लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेंगे। ये हैं 1. राजकोट (गुजरात) 2. रांची (झारखंड) 3. इंदौर (मध्य प्रदेश) 4. चेन्नई (तमिलनाडु) 5. अगरतला (त्रिपुरा) और 6. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
2. तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और इटली की तकनीकों सहित 25 देशों की 32 नई प्रौद्योगिकियों के साथ 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं का मूल्यांकन किया गया था।

3. विजेता राज्यों सहित, अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रौद्योगिकी अपनाये जाने की उम्मीद है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अन्य मिशन और निर्माण से संबंधित अन्य मंत्रालय भी सीटीआई-2019 में प्रदर्शित आधुनिक और नवीन तकनीकों को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।
4. जून, 2019 के लिए लाइटहाउस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आशा- इंडिया उन संभावित प्रौद्योगिकी संस्थाओं संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जो उन्हें बाजार के अनुकूल और मापनयोग्य बनाने के लिए मेंटरशिप, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और त्वरण मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं।
5. 55 पोस्ट-प्रोटोटाइप और 23 पूर्व-प्रोटोटाइप के साथ देश भर के 78 संभावित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने विशेषज्ञ जूरी को अपनी प्रस्तुतियां दीं, जिसमें मुंबई से रोबोटिक मोबाइल कंस्ट्रक्शन, बैंगलोर से निर्माण के क्षेत्र में 3डी प्रिंटिंग, हेम्पकार्ट कंस्ट्रक्शन सिस्टम से प्रस्तुतियां शामिल थीं।
6. अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सप्लेरेटर विशेषज्ञ जूरी द्वारा चयनित किये जाने वाले संभावित विचारों/उत्पादों/तकनीकों को सहायता प्रदान की जाएगी और इसे मार्केट-रेडी बनाने में मदद की जाएगी।
7. **कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया (सीटीआई) एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होगा।** एनएआरईडीसीओ और सीआरईडीएआई इस आयोजन में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सहयोग ले रहे हैं।
8. यह कार्यक्रम निर्माण क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय इवेंट कैलेंडर में एक नियमित स्थान बनाएगा, जहां दुनिया भर में इस क्षेत्र की अग्रणी संस्थाएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी।
9. प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष, **अप्रैल-2019 से मार्च, 2020 तक 'निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष'** 'निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष' घोषित किया। इस जीएचटीसी-इंडिया के तहत शुरू की गई गतिविधियों का उपयोग करने के लिए कार्यान्वयन की गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई जा रही है और निर्माण क्षेत्र को अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का विचार किया जा रहा है।
10. कुछ गतिविधियों यों में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) भी शामिल होगा, ताकि युवा पीढ़ी तकनीकी प्रगति से परिचित हो।

निवेशकों को नई तेल व गैस नीति से लुभाने की कोशिश

सरकार ने तेल एवं गैस खोज क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए इससे जुड़ी नीति में अहम बदलाव किए हैं। नई नीति के तहत सरकार नए एवं कम खोजे गए क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन उत्पादन पर संबंधित कंपनी से लाभ में हिस्सा नहीं मांगेगी। हर तरह के बेसिन के लिए एक समान अनुबंध वाली दो दशक पुरानी नीति में बदलाव करते हुए नई नीति में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इसके तहत पहले से उत्पादन वाले क्षेत्रों और नए क्षेत्रों के लिए नियम अलग-अलग रहेंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उत्पादकों को भविष्य में बोली के दौरान तेल एवं गैस के लिए विपणन और कीमत (मार्केटिंग एंड प्राइसिंग) के मामले में आजादी होगी। इस प्रक्रिया में इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बेसिन कैसा है।

क्या है

1. **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी को नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी।** इसमें कहा गया है कि भविष्य में सभी तेल एवं गैस क्षेत्र या ब्लॉक का आवंटन प्राथमिक रूप से खोज कार्यों को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा।
2. **नए नियम के तहत कंपनियों को श्रेणी-एक के अंतर्गत आने वाले सेडीमेंटरी बेसिन से होने वाली आय का एक हिस्सा देना होगा।** इसमें कृष्णा गोदावरी, मुंबई अपतटीय, राजस्थान या असम के क्षेत्र शामिल हैं, जहां वाणिज्यिक उत्पादन पहले से हो रहा है।
3. वहीं कम खोज वाले श्रेणी-दो और तीन बेसिन के लिए कंपनियों से केवल मौजूदा दर पर रॉयल्टी ली जाएगी। इसमें कहा गया है कि जमीन और उथले जल क्षेत्र में स्थित ब्लॉक में चार साल तथा गहरे जल क्षेत्र में अनुबंध की तारीख से पांच साल के भीतर उत्पादन शुरू किया जाता है तो रियायती दर से रॉयल्टी देनी होंगी। होंगे।

4. दो दशक पहले हुई थी बोली की शुरुआत: सरकार ने 1999 में 'नई खोज लाइसेंसिंग नीति' (नेल्प) के तहत तेल एवं गैस ब्लॉक के लिए बोली आमंत्रित करने की शुरुआत की थी।
5. इसमें ब्लॉक उन कंपनियों को आवंटित किए जाते थे जो अधिकतम कार्य की प्रतिबद्धता जताती थीं। लेकिन कंपनियों को उन क्षेत्रों में खोज तथा अन्य कार्यों पर आने वाली अपनी लागत निकलने के बाद लाभ को सरकार के साथ साझा करना होता था।
6. दो साल पहले भाजपा सरकार ने इस नीति के स्थान पर हाइड्रोकार्बन खोज एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को पेश किया। इसमें विभिन्न न्न स्तर की कीमत एवं उत्पादन के आधार पर अधिकतम राजस्व की पेशकश करने वाली कंपनियों को ब्लॉक आवंटित करने का प्रावधान था। एचईएलपी की नीति भी उत्पादन बढ़ाने या नए निवेशकों को लाने में विफल रही।

मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें सबसे अमीर शख्स

भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में भी आगे बढ़ रहे हैं। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में वह छह पायदान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में जेफ बेजोस इस बार भी पहले स्थान पर कायम काबिज रहे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक ऐमजॉन के संस्थापक, 55 वर्षीय जेफ बेजोस इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उनके बाद बिल गेट्स और वारेन बफे का स्थान है। बेजोस की संपत्ति पिछले एक साल में 19 अरब डॉलर बढ़कर 131 अरब डॉलर हो गई। मुकेश अंबानी (61 वर्ष) की संपत्ति 2018 में 40.1 अरब डॉलर थी जो कि बढ़कर 50 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। दुनिया के अमीरों में पिछले साल वह 19 वें स्थान पर थे और इस साल वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि, उनके भाई अनिल अंबानी इस सूची में कहीं नीचे 1349 वें स्थान पर हैं।

क्या है

1. गौरतलब है कि 2017 की फोर्ब्स पत्रिका की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान 33वां था। फोर्ब्स की सूची में शामिल भारत के 106 अरबपतियों में मुकेश अंबानी सबसे आगे हैं।
2. विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी 22.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 36 वें स्थान पर हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र रेत की प्रमुख कंपनी एचसीएल के सह-संस्थापक शिव नाडर 82वें और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ लक्ष्मी मित्तल 91वें स्थान पर रहे। ये सभी दुनिया के शीर्ष -100 अरबपतियों में शामिल हैं।
3. वैश्विक अरबपतियों की सूची में भारत के आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला (122वें स्थान), अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक गौतम अडानी (167वें), भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल (244 वां स्थान), उपभोक्ता सामान कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण (365वें), पीरामल एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष अजय पीरामल (436वें स्थान), बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ (617वें स्थान), इंफोसिस के सह-संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति (962वें स्थान) और आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी (1349वें स्थान) का नाम शामिल है।
4. फोर्ब्स ने कहा कि मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं और पत्रिका की वर्ष 2018 की शक्तिशाली लोगों की सूची में वह 32 वें स्थान पर थे। उन्हें 2017 में 'ग्लोबल गेम चेंजर' का दर्जा भी दिया गया था।

एनएबीएल द्वारा गुणवत्ता आश्वासन योजना का शुभारंभ

छोटी प्रयोगशालाओं को बुनियादी रूप से योग्य गुणवत्ता प्रक्रियाओं के लिए संवेदी बनाने के लिए एनएबीएल ने बेसिक कंपोजिट (बीसी) चिकित्सा प्रयोगशालाओं (प्रवेश स्तर) के लिए फरवरी, 2019 में गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएएस) नामक एक अन्य स्वैच्छिक योजना का शुभारंभ किया है। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड काउंट्स, सामान्य संक्रमणों के लिए त्वरित परीक्षण, लिवर और गुर्दे के कार्य परीक्षण तथा मूत्र के नियमित परीक्षण जैसे ही बुनियादी नियमित परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाएं इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र होंगी। छोटी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने

के लिए इस योजना का आधार मानदंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 18 मई, 2018 को जारी राजपत्र अधिसूचना में सूचीबद्ध की गई जरूरतों पर आधारित होगा। यह अधिसूचना नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियमावली, 2012 में संशोधन के लिए जारी की गई थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम दस्तावेज और नाम मात्र का शुल्क निर्धारित किया गया है। परीक्षण परिणामों की गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता आंकलन आकलन के घटक जोड़े गए हैं।

क्या है

1. यह योजना भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में, जहां प्रयोगशालाएं अपनी सभी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता की अनिवार्यताओं का अनुपालन करती हैं, जमीनी स्तर पर गुणवत्ता लाने में मदद करेगी।
2. इससे गुणवत्ता की आदत विकसित होने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं को एक निश्चित समय में आईएसओ 15189 की बैंच मार्क मान्यता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
3. प्रयोगशालाएं किसी भी निश्चित समय में आईएसओ 15189 के अनुसार मान्यता प्राप्ति के लिए अपग्रेड की जा सकती हैं। सफल प्रयोगशालाओं को एनएबीएल द्वारा क्यूएस बीसी योजना के अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
4. उन्हें एक निश्चित समय सीमा के लिए बुनियादी मानक के पृष्ठांकन के चिन्ह के रूप में अपनी परीक्षण रिपोर्टों पर एक विशिष्ट प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन इससे पहले उन्हें आईएसओ 15189 के अनुसार पूर्ण मान्यता की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
5. यहां तक कि देश के दूर-दराज के हिस्सों में स्थित अधिक से अधिक छोटी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए एनएबीएल देश के विभिन्न शहरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।
6. इस योजना से अगले 5 वर्षों में अधिक से अधिक प्रयोगशालाओं में भारी बदलाव लाने के लिए प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता युक्त सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों के क्लिनिकों, छोटी प्रयोगशालाओं और छोटे नर्सिंग होम की प्रयोगशालाओं को भी गुणवत्ता युक्त प्रयोगशाला के परिणामों तक पहुंच उपलब्ध होगी।
7. राज्य सरकारों को नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठान के रूप में प्रयोगशालाओं का पंजीकरण कराने के लिए इस प्रवेश स्तर योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अभी तक यह अधिनियम 11 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इससे इन राज्यों में निदान के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी।
8. यह योजना भारत सरकार की आयुष्मान योजना को बहुत जरूरी समर्थन देगी। इस योजना के तहत सरकार ने 1,50,000 कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
9. इस में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार शामिल किये जायेंगे। एनएबीएल की इस प्रवेश स्तर योजना से विशेष रूप से गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले अधिकांश नागरिकों को गुणवत्ता युक्त निदान सुविधा उपलब्ध कराकर गुणवत्ता चिकित्सा देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना की वैश्विक पहुंच के लक्ष्य को भी बढ़ाने में मदद करेगी।

एनजीओ का विदेशी चंदा में 40 फीसद की कमी

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से मिलने वाले चंदे में पिछले चार वर्षों में 40 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी परामर्शदाता फर्म बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्रालय ने 13 हजार से अधिक एनजीओ के लाइसेंस रद्द रद्द किए। रिपोर्ट में कहा गया है, 'विदेशी चंदे में करीब 40 फीसद कमी आई है। विदेशी चंदे को अधिनियमित करने वाले एफसीआरए के उल्लंघन पर सरकार द्वारा एनजीओ पर की गई कार्रवाई के कारण ऐसा हुआ।

क्या है

1. कई संगठनों ने सरकारी कार्रवाई का विरोध किया और इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। मोदी सरकार ने पिछले साल रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर का कार्यकाल कम कर दिया था। मोर भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निदेशक हैं।
2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने मोर को हटाने के लिए अभियान चलाया था।
3. फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े विदेशी एनजीओ को भी सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस दौरान समाजसेवियों का निजी योगदान बढ़ा है।

फ्लैशबैक

1. गैर सरकारी संगठन (NGO) एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित गैर सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
2. उन मामले में जिनमें गैर सरकारी संगठन पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारों द्वारा निधिबद्ध होते हैं, NGO अपना गैर-सरकारी पद ओहदा बनाए रखता है और सरकारी प्रतिनिधियों को संगठन में सदस्यता से बाहर रखता है।
3. शब्द इंटरगवर्नमेंटल ओर्गेनाइजेशन के विपरीत, 'गैर सरकारी संगठन' एक आम उपयोग का शब्द है, लेकिन एक कानूनी परिभाषा नहीं है। कई न्यायालयों में इस प्रकार के संगठनों को 'नागरिक समाज संगठन' के रूप में परिभाषित किया जाता है या अन्य नामों से निर्दिष्ट किया जाता है।
4. अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या 40,000 है। राष्ट्रीय संख्या और भी अधिक है: रूस में 277,000 गैर सरकारी संगठन हैं। भारत में 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है।

विज्ञान एवं तकनीकी

पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज

भारतीय शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मेंढक मेंढक की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों में होने वाले बदलावों और जैविक विकास के क्रम में मेंढक मेंढक की यह प्रजाति करीब छह से सात करोड़ वर्ष पहले अपने पूर्वजों से अलग हो गई थी। मेंढक की इस प्रजाति को ऐस्ट्रोबैट्राकस कुरिचिआना नाम दिया गया है और इसे नए ऐस्ट्रोबैट्राकिने उप-परिवार के तहत रखा गया है। इस मेंढक के शरीर के दोनों किनारों पर मौजूद चमकदार धब्बे पाए जाते हैं, जिसे रेखांकित करने के लिए इस नई प्रजाति के नाम में ऐस्ट्रोबैट्राकस जोड़ा गया है।

क्या है

1. केरल के वायनाड में, जहां इस प्रजाति के नमूने पाए गए हैं, वहां के स्थानीय कुरिचिआ आदिवासियों के सम्मान में इसके नाम में कुरिचिआना शामिल किया गया है। मेंढक की यह प्रजाति वायनाड के कुचियारमाला चोटी के नाम से जानी जाती रही है, जो वायनाड के घने जंगलों में पत्तियों के ढेर ढेर के नीचे रहती है।

दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीका के मेंढकों की जैसी है संरचना

1. शोधकर्ताओं ने बताया कि नए वंश और नए उप-परिवार से संबंधित अज्ञात प्रजातियों की खोज दुर्लभ है। आणविक विश्लेषण से पता चला है कि इस नई प्रजाति के पूर्वज जैविक विकास के क्रम में लगभग 6-7 करोड़ साल पूर्व अलग हो गए थे।
2. ऐस्ट्रोबैट्राकस मेंढक प्रायद्वीपीय भारत में पाया गया है, लेकिन इसके रूप एवं आकृति (विशेषकर त्रिकोणीय अंगुली और पैर की अंगुली की युक्तियां) दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीका के मेंढकों जैसी दिखती है।
3. प्रोफेसर कार्तिक शंकर ने बताया कि पश्चिमी घाट में मेंढक वंश के सबसे पुराने जीवित सदस्यों से जुड़ी यह एक दुर्लभ खोज है।

2. यह अध्ययन भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुणे, फ्लोरिडा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एवं जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पश्चिमी घाट में रेंगेने वाले और उभयचर जीवों की विविधता को उजागर करने के लिए किए गए एक सर्वेक्षण में मेंढक की इस प्रजाति के नमूने पाए गए हैं।
3. बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सहायक प्रोफेसर कार्तिक शंकर और उनके शोधार्थी एसपी विजयकुमार द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में पश्चिम घाट के विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों, अलग-अलग वर्षा क्षेत्रों, विविध प्रकार के आवास में रहने वाले सरीसृप और उभयचर जीव शामिल थे।
4. अध्ययनकर्ताओं में शामिल विजय कुमार ने बताया कि पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले निकटीबैट्राकिने और श्रीलंका के लैंकैनेक्टिने मेंढक डक इस नई प्रजाति के करीबी संबंधियों में शामिल हैं। निकटीबैट्राकिने प्रजाति का संबंध निकटीबैट्राकस वंश से है, जबकि लैंकैनेक्टिने मेंढक डक लैंकैनेक्टेस वंश से संबंधित है।
5. शोधकर्ताओं ने फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की ओपनवर्टेब्रेट परियोजना (ओवर्ट) के अंतर्गत उपलब्ध नमूनों का उपयोग करते हुए अन्य प्रजातियों के मेंढकों ढकों के कंकाल से नई प्रजाति की तुलना की है।
6. मेंढक डक के रूप एवं आकार संबंधी तुलनात्मक विवरण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के मेंढकों के आनुवंशिक विश्लेषण के आंकड़ों के उपयोग से नए मेंढक के संबंधियों की पहचान हुई।

एस्ट्रोसैट ने खोजा सितारों का नया समूह

सितंबर 2015 में प्रक्षेपित की गई भारतीय मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' निरंतर रोमांचक जानकारीयों दे रही है। इस वेधशाला का उपयोग करते हुए तिरुवनंतपुरम और मुंबई के खगोलविदों ने तारों के गोलाकार गुच्छे (ग्लोब्यूलर क्लस्टर) एनजीसी-2808 में पराबैंगनी तारों की एक नई श्रेणी की खोज की है। तारों के गोलाकार गुच्छों (ग्लोब्यूलर क्लस्टर) में हजारों से लाखों तारे होते हैं, इन तारों के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप वह गुच्छा अपनी आकृति बनाए रखता है और यह माना जाता है कि इन सब तारों का जन्म लगभग एक ही समय में एक साथ हुआ होगा।

क्या है

1. हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 150 गोलाकार गुच्छे हैं। इनमें से कुछ संभवतः आकाशगंगा के सबसे पुराने पिण्ड होंगे। तारे जन्म लेते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। विकास की इन विभिन्न स्थितियों के आने में जो समय लगता है वह हमारी कल्पना से परे है।
2. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइएसटी) तिरुवनंतपुरम में एमएससी के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र और अनुसंधान दल की सदस्य राशि जैन ने बताया कि बड़े द्रव्यमान वाले तारे तेजी से विकास करते हैं, फिर कुछ लाख वर्षों तक प्रकाशित रहकर एक अत्यंत दर्शनीय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जबकि, हमारे सूर्य या उससे छोटे तारे अरबों वर्षों में धीरे- धीरे विकसित होते हैं।
3. शोध का नेतृत्व करने वाली आइआइएसटी की प्रोफेसर सरिता विग ने कहा कि चूंकि तारों के एक गोलाकार गुच्छे में विभिन्न द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, जिनकी रासायनिक संरचना लगभग समान होती है।
4. इसलिए किसी समय हम इनमें एक साथ अपने विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न द्रव्यमानों के तारों की अवस्था देख सकते हैं। आज से 5 अरब वर्ष बाद जब सूर्य लाल रंग का विशाल दानव तारा बन जाएगा तो वह इन्हीं तारों जैसी अवस्थाओं से गुजरेगा। जो तारे सूर्य से अधिक बड़े होते हैं उनका विकास क्रम बहुत भिन्न होता है और वे अंततः पराबैंगनी प्रकाश में उज्ज्वल तजच्च्वल होते हैं क्योंकि वे अधिक गर्म होते हैं।

शोधकर्ताओं ने इस तरह से किया अध्ययन

1. शोधकर्ताओं ने बताया एनजीसी-2808 सबसे विशाल गोलाकार समूहों में से एक है और हमसे 47,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

2. इस समूह का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं के दल ने एस्ट्रोसैट में लगी अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (यूवीआईटी) का उपयोग किया।
3. एनजीसी-2808 के इस चित्र में दूरस्थ पराबैंगनी उत्सर्जन को नीले और निकटवर्ती पराबैंगनी उत्सर्जन को पीले रंग में दर्शाया गया है।
4. शोधकर्ताओं को विभिन्न पराबैंगनी फिल्टरों के माध्यम से ली गई छवियों में 12,000 से अधिक तारों की अलगअलग पहचान करने में सफलता मिली है।
5. यूवीआईटी पर पराबैंगनी फिल्टरों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने प्रत्येक फिल्टर में उनकी चमक के आधार पर गर्म तारों के विभिन्न समूहों को अलग करने का प्रयास किया और अपेक्षानुसार रूप प्रत्येक विकासवादी चरण में तारों की पहचान करने में सफल रहे।

एड्स फ्री मरीज का दूसरा मामला

एड्स वायरस का इलाज करने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि लंदन के एक एचआईवी पॉजिटिव शख्स को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए सफलतापूर्वक एड्स वायरस से मुक्त करा लिया गया है। एड्स से ठीक होने वाला यह दुनिया का दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति एक जर्मन था जो बर्लिन पेशेंट के नाम से मशहूर हुआ था। इसे 2008 में एड्स मुक्त करार दिया गया था। बाद में टिमोथी ब्राउन नामके इस शख्स ने अपनी पहचान उजागर कर दी थी।

क्या है

1. फिलहाल, लंदन के इस रोगी का नाम उजागर नहीं किया गया है। इस रोगी को 2003 में पता चला था कि वह एचआईवी से ग्रस्त है लेकिन उसने 2012 में इस इन्फेक्शन का इलाज कराना शुरू किया था। उसे 2012 में Hodgkin lymphoma नाम का कैंसर हुआ जिसका 2016 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज शुरू हुआ।
2. उसके कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों को स्टेम सेल का ऐसा डोनर मिला जिसके शरीर में एक ऐसा दुर्लभ जीन म्यूटेशन हुआ था जो प्राकृतिक तौर पर एचआईवी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता मुहैया कराता है।
3. यह जानकारी होने पर डॉक्टरों को लगा कि कैंसर के साथ-साथ इसके एचआईवी का भी इलाज हो जाएगा। यह जीन म्यूटेशन उत्तरी उत्तरी यूरोप में रहने वाले महज एक प्रतिशत लोगों में होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता रविंद्र गुप्ता का कहना है, 'ऐसा जीन मिलना लगभग असंभव घटना है।'
4. इस ट्रांसप्लांट से लंदन के इस पेशेंट की पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली ही बदल गई जिससे डोनर की ही तरह उसका शरीर भी एचआईवी वायरस के खिलाफ बेअसर हो गया।
5. इसके बाद इस मरीज ने स्वेच्छा से एचआईवी की दवाएं लेना बंद कर दीं ताकि यह देखा जा सके कि कहीं एड्स वायरस फिर से तो सक्रिय नहीं हो जाएगा। आमतौर पर दवा बंद करने के दो से तीन हफ्तों में वायरस फिर सक्रिय हो जाता है। लेकिन लंदन के मरीज के साथ ऐसा नहीं हुआ। दवा बंद करने के 18 महीनों के बाद भी उसके शरीर में एड्स वायरस नहीं पाया गया।

मंगल पर प्राचीन भूजल प्रणाली के साक्ष्य

वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर ऐसी प्राचीन झीलों का भूगर्भीय साक्ष्य ढूंढा है, जो आपस में जुड़ी थीं और जिनका अस्तित्व कभी इस लाल ग्रह की सतह के नीचे गहरे तक रहा होगा। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इनमें से पांच झीलों में संभवतः जीवन के लिए आवश्यक खनिज लवण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर ऐसी प्राचीन

झीलों का भूगर्भीय साक्ष्य ढूँढा है, जो आपस में जुड़ी थीं और जिनका अस्तित्व कभी इस लाल ग्रह की सतह के नीचे गहरे तक रहा होगा।

क्या है

1. नीदरलैंड में उट्रेच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल एक शुष्क ग्रह लगता है लेकिन इसकी सतह ऐसे संकेत देती है जिनसे उन संभावनाओं को बल मिलता है कि कभी इस ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पानी रहा होगा। पिछले साल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस अभियान में ग्रह के दक्षिणी ध्रुव रुव की निचली सतह में तरल अवस्था में पानी के कुंड का पता चला था।
2. जियोफिजिकल रिसर्च : प्लेनेट्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन में प्राचीन काल में मंगल पर भूजल के विस्तार का खुलासा किया गया था जो इससे पहले सिर्फ मॉडल के जरिए अनुमान लगाया जाता था।
3. उट्रेच यूनिवर्सिटी से फ्रांसेस्को सैलेसी ने कहा, 'पहले मंगल पानी से भरा ग्रह था। लेकिन जैसे-जैसे इसकी जलवायु बदली, इस पर मौजूद जल रिसकर सतह के नीचे चला गया और भूजल का रूप ले लिया'। सैलेसी ने एक बयान में कहा, 'हमलोगों ने अपने अध्ययन में इस पानी की पहचान की है। इसकी भूमिका बहस का विषय है। हमने मंगल पर व्यापक भूजल का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया'।
4. अनुसंधानकर्ताओं ने मंगल के उत्तरी गोलाध्वं में मौजूद गड्ढों गड्ढों में ऐसे 24 गहरे स्थानों की पड़ताल की, जो उसके अनुमानित समुद्र तल से 4000 मीटर नीचे थे।
5. वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल की सतह पर मौजूद इन गड्ढों में ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण तभी हो सकता है जब वहां जल मौजूद हो। समझा जाता है कि करीब तीन और चार अरब वर्ष पहले मंगल पर समुद्री जीवन मौजूद था।
6. इटली के वैज्ञानिक गियान गैबरिएल ओरी ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह समुद्र संभवतः समूचे ग्रह में फैली भूजलीय झीलों की प्रणाली से जुड़ा हो'। ओरी ने कहा, 'ऐसी संभावना है कि ये झीलें करीब 3.5 अरब साल पहले ग्रह पर मौजूद थीं। इसलिए उस समय समुद्री जीवन होने की संभावना हो सकती है'।

1658 बी के अस्तित्व की पुष्टि

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर अंतरिक्ष टेलिस्कोप के लॉन्च के 10 साल बाद उसके द्वारा पता लगाए गए पहले सौरिय सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रह के सच में मौजूद होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केपलर-1658 बी के तौर पर पहचाना जाने वाला यह बाहरी ग्रह विशाल गर्म बृहस्पति ग्रह के समान है जो हर 3.85 दिन में अपने ग्रह के इर्द-गिर्द घूमता है।

क्या है

1. उन्होंने बताया कि सतह से यह ग्रह सूरज के व्यास से 60 गुणा ज्यादा बड़ा मालूम होता है। केपलर 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद से पारगमन विधि के माध्यम से हजारों बाहरी ग्रहों की खोज कर चुका है।
2. इस तरीके में किसी ग्रह के सामने से गुजरने के दौरान सितारे की चमक में आई मामूली कमी को दर्ज किया जाता है।
3. एस्ट्रोनामिकल पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अन्य वस्तुएं इस तरीके की नकल कर सकती हैं इसलिए केपलर डेटा ग्रहों जैसे लगने वाली वस्तुओं की पहचान करता है लेकिन उन्हें सचमुच ग्रह साबित करने के लिए और अधिक विश्लेषण की जरूरत पड़ती है।
4. केपलर द्वारा 2011 में खोजा गया पहला ग्रह होने के बावजूद केपलर-1658 बी की पुष्टि की राह बहुत मुश्किल भरी रही। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि यह ग्रह सूर्य से तीन गुणा ज्यादा बड़ा एवं 50 प्रतिशत ज्यादा विशाल है।

स्पेसएक्स रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हुआ ड्रैगन कैप्सूल

अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली अमेरिका की निजी कंपनी 'स्पेसएक्स' का नया क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल 2 मार्च 2019 को अपने 'फाल्कन 9 रॉकेट' के जरिए फ्लोरिडा से सफल प्रक्षेपण के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र

रवाना हो गया। प्रक्षेपण के दौरान यान पर 'रिप्ले' नामक एक डमी बैठाया गया था। यह प्रक्षेपण पहले मानवयुक्त प्रायोगिक यान के लिए अभ्यास के तौर पर किया गया है।

क्या है

1. इस साल के अंत तक नासा के दो अंतरिक्षयात्रियों के साथ स्पेसएक्स के यान के अंतरिक्ष में जाने की संभावना है।
2. 'स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नॉलजी कॉर्पोरेशन' को 'स्पेस एक्स' के नाम से जाना जाता है। यह एक निजी अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है।
3. स्पेसएक्स ने बाद में फाल्कन लॉन्च वाहन परिवार और ड्रैगन अंतरिक्ष यान परिवार विकसित किया है, जो वर्तमान में पृथ्वी कक्षा में पेलोड वितरित करता है।
4. देर रात करीब दो बजकर 49 मिनट पर (अंतर्राष्ट्रीय रराष्ट्रीय समयानुसार सुबह सात बजकर 49 मिनट पर) केप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट प्रक्षेपित किया गया।
5. प्रक्षेपण के दौरान जोरदार धमाके से फ्लोरिडा तट रोशन शैशन हो गया था। इसके करीब 11 मिनट बाद स्पेसएक्स मिशन नियंत्रण ने 'ड्रैगन के रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग होने की पुष्टि की।'
6. घटना से कंपनी के मुख्यालय और कैनेडी स्पेस सेंटर में लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस कैप्सूल के 3 मार्च 2019 अंतर्राष्ट्रीय रराष्ट्रीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय रराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है और 8 मार्च 2019 तक इसके धरती पर लौटने की संभावना है।

नया क्रू कैप्सूल पहुंचा अंतरिक्ष स्टेशन

स्पेस एक्स का नया क्रू कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय यराषरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है और इसने एक ही दिन में मील का नया पत्थर स्थापित किया है। इस ड्रैगन कैप्सूल को जब 2 मार्च 2019 को उसके पहली परीक्षण उड़ान पर भेजा गया तब उस पर कोई सवार नहीं था, उसमें बस डमी थीं।

क्या है

1. ड्रैगन बहुत ही सफाई से 3 मार्च 2019 की सुबह आईएसएस पहुंच गया। यदि यह छह दिनों का डेमो सफल हो जाता है तो स्पेस एक्स नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत इस साल गर्मी में दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जा सकता है।
2. ये दोनों अंतरिक्ष यात्री कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल में इस सारी गतिविधि को देख रहे थे। क्रू ड्रैगन आईएसएस के रोबोट हैंड की मदद के बिना ही स्वयं आईएसएस तक पहुंच गया।

विविध

अमेठी में बनेगी दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंडो-रूस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बता दें कि इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत की आयुध फैक्ट्री और रूस के प्रतिष्ठान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। कोरवा आयुध फैक्ट्री में प्रतिष्ठित कलाशनिकोव राइफलों की नवीनतम श्रेणियां बनाई जाएंगी। यह संयुक्त उद्यम देश में शस्त्र सेनाओं को मदद देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा।

क्या है

1. सेना को एके-47 राइफल(AK-47 rifle) का आधुनिक वर्जन एके-203(AK-203) से परिवर्तित लैश किया जाएगा। इसके लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। इस करार के अनुसार, रूस के सहयोग से भारत में सात लाख 50 हजार (750,000) असॉल्ट राइफलें बनेगी।

- एके-203 असॉल्ट राइफलों के लिए ओएफबी और रूसी कंपनी कंसर्न क्लानिशनकोव के बीच रक्षा सौदे पर करार हुआ है। भारत और रूस की कंपनियां मिलकर इसे बनाएंगी। भारतीय सेना की पुरानी इंसास राइफल को हटाया जाएगा रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह जवानों को एके-203 असॉल्ट राइफलें प्रदान की जाएगी। मिलेंगी।
- रूस ने दस साल पहले भारतीय सेना के लिए AK-47 राइफल के नए वर्जन की पेशकश की थी। उस समय दोनों देशों के बीच ज़ख़103 राइफल पर बात हुई थी लेकिन डील पक्की नहीं हो पायी थी।
- अब भारत सरकार और रूस के बीच 2018 का मॉडल AK-203 पर सहमति बनी है। बताया जाता है कि AK सीरीज की यह सबसे खतरनाक राइफल है।

क्यों खास है एके-203

- यह एके फैमिली की सबसे अपडेट राइफलों में एक है। अपनी एक्युरैसी के लिए मशहूर एके-203, कंटवर्टेबल राइफल है।
- इसे सैमी ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एके-47 सबसे बेसिक मॉडल है इसके बाद एके में 74, 56, 100 सीरीज, 200 सीरीज आ चुकी है।
- यह भी 201, 202 की तरह राइफल है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई असॉल्ट राइफल की लंबाई करीब 3.25 फुट होगी। गोलियों से भरी राइफल का वजन लगभग 4 किलोग्राम होगा। साथ ही यह किसी भी ऑपरेशन में जवानों के लिए चलानी आसान होगी इजी टू हैंडल होगी। यह नाइट रात्रि ऑपरेशन में भी काफी कारगर होगी।
- इससे पहले अभी हाल में ही भारत ने अमेरिका से 72,400 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए समझौता किया था। करीब 700 करोड़ रुपये में ये राइफलें खरीदी जाएंगी। अनुबंध के मुताबिक एक साल के भीतर अमेरिका की सिग सौथर कंपनी 7.62 एमएम की 72,400 राइफलें देगी। इन राइफलों के मिलने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी।
- अभी भारतीय सेना के पास 5.56 गुणा 45 एमएम इंसास राइफलें हैं। इन्हें आधुनिक और उन्नत तकनीक वाली 7.62 गुणा 51 एमएम राइफल से बदलना आवश्यक हो गया था। चीन से लगती 3,600 किलोमीटर की लंबी सीमा पर तैनात जवान इस राइफल का इस्तेमाल करेंगे।

पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार

भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वर्तमान को 'भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। वह अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा शुरू किए गए 'भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार' पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। संगठन के एक पदाधिकारी ने 3 मार्च 2019 को यह जानकारी दी।

क्या है

- मिग-21 बाइसन के पायलट अभिनंदन ने 27 फरवरी को हवाई लड़ाई में पाकिस्तानी वायु सेना के एफ-16 विमान को मार गिराया था।
- इसके बाद मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच अभिनंदन सुरक्षित विमान से बाहर निकल गए थे। उनका पैराशूट पीओके में गिरा जिसके तुरंत बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा। दो दिन पहले शुक्रवार को ही वह स्वदेश लौटे हैं।
- संगठन की महाराष्ट्र इकाई के संयोजक पारस लोहाड़े ने कहा कि संगठन के अध्यक्ष मणींद्र जैन ने लड़ाकू विमान के पायलट को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की।
- लोहाड़े ने कहा कि इसी साल शुरू किए गए इस पुरस्कार के तहत 2.51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह ह और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
- 17 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर अभिनंदन को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

मिसाइल सिस्टम पुरस्कार

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित मिसाइल सिस्टम पुरस्कार से नवाजा गया है। मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स ने दिया है।

क्या है

1. रेड्डी को यह पुरस्कार एरिजोना स्थित रेथन मिसाइल सिस्टम के रेंडल जे विल्सन और वर्जीनिया स्थित प्रोफेशनल सोसाइटी ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ प्रदान किया गया।
2. बता दें कि 55 वर्षीय रेड्डी को पिछले साल ही डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया था। यह पुरस्कार विषम संख्याओं वाले वर्षों में हर दो वर्ष में एक बार दिया जाता है।
3. मिसाइल सिस्टम प्रौद्योगिकी को विकसित करने और क्रियान्वित करने में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।

2022 एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल

एशियाई खेल 2022 में T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के महासचिव राजीव मेहता ने 4 मार्च 2019 को इस बात की जानकारी दी। अब साफ है कि 2022 में हांगकंग में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में एशिया महाद्वीप की क्रिकेट टीमों T20 क्रिकेट में हिस्सा लेंगी। इससे पहले क्रिकेट को 2010 और 2014 एशियाई खेलों में जगह मिली थी लेकिन इंडोनेशिया में 2018 में हुए खेलों में क्रिकेट को जगह नहीं दी गई।

क्या है

1. हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम इन खेलों में हिस्सा लेगी या नहीं इस पर बीसीसीआई की ओर से स्पष्टीकरण आना बाकी है। भारत इससे पहले टीम के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता से बाहर रह चुका है।
2. जब 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था, तब बीसीसीआई ने व्यस्त दिनचर्या ति बिजी शेड्यूल होने की बात कहकर अपनी टीम इन खेलों में भेजने से इनकार कर दिया था।
3. हालांकि एशियाई खेलों के अगले टूर्नामेंट टूर्नामेंट के आयोजन में अब काफी समय है और ऐसे में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व पर चर्चा करने के लिए बीसीसीआई को काफी समय मिलेगा।
4. भारत को छोड़कर श्री श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे रेग्यूलर क्रिकेट खेलने वाले देश इन खेलों में हिस्सा ले चुके हैं।
5. श्री श्रीलंका और पाकिस्तान ने 2014 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे, जबकि 2010 में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बाजी मारी थी।

वैश्विक वायु प्रदूषण 2018

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वायु प्रदूषण 2018 की रिपोर्ट में नयी दिल्ली को 62 प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से 5 मार्च 2019 को जारी किया गया। रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता को पीएम 2.5 के संदर्भ में मापा गया है। इस रिपोर्ट में चीन के शहरों की हवा सुथरी धरी है और वहां सुधार देखने को मिला है।

क्या है

1. पर्यावरण क्षेत्र के गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की तरफ से हाल में किए गए अध्ययन में राजधानी दिल्ली से सटा गुरुग्राम दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है।
2. पिछले साल को दो महीनों में गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 का स्तर 200 से ऊपर ही पाया गया था। यह स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि इसका स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

- रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण अगले साल तक करीब 70 लाख लोग समय से पहले मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसके अलावा इसका अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा।
- दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर लाहौर, 11वें नंबर पर दिल्ली और 17वें नंबर पर ढाका है।

केवल छह देशों में महिलाओं को है पूर्ण अधिकार

नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को समानता का अधिकार, एक ऐसा विषय है जिसे लेकर भारत समेत दुनिया भर में लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों से लेकर कस्बाई स्तर तक कवायद की जा रही है। बावजूद आज भी ये सवाल खड़ा है कि क्या महिलाओं को पुरुषों की तरह आजादी मिल चुकी है। ऐसे में लैंगिंग समानता पर विश्व बैंक द्वारा दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति पर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 'वूमन, बिजनेस एंड द लॉ 2019' (Women, Business and the Law 2019) के अनुसार दुनिया लैंगिंग समानता की ओर बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इस रफ्तार से अगले 50 साल (वर्ष 2073) तक भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं हो सकेगा। वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल छह ऐसे देश हैं, जहां सही मायनों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। इन देशों में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लक्समबर्ग और स्वीडन देश शामिल हैं।

क्या है

- रिपोर्ट में इन देशों को महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार अधिकारी देने के लिए पूरे 100 नंबर दिए गए हैं। इन छह शीर्ष देशों में फ्रांस ने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सुधार किया है।
- फ्रांस ने घरेलू हिंसा कानून (Domestic Violence Law), कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न गंभीर अपराध और अभिभावकों को वैतनिक अवकाश जैसे फैसलों का अहम योगदान है।
- इसी तरह 100 नंबर के साथ पहले पायदान पर मौजूद देशों ने भी महिलाओं को पुरुषों को बराबर अधिकारी दिलाने के लिए कई बड़े और अहम कानून बनाए हैं।
- लैंगिंग समानता को लेकर किए गए अध्ययन में पूरी दुनिया औसत अंक 74.71 है। मतलब विश्वभर में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले मात्र 75 फीसद अधिकार ही प्राप्त हैं।
- इसके विपरीत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के सब सहारा देशों को विश्व बैंक के अध्ययन में औसत 47.37 अंक ही हासिल हुए हैं। मतलब इस क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम अधिकारी प्राप्त हैं।
- इस अध्ययन का उद्देश्य ये बताना है कि कैसे कानूनी अड़चनें महिलाओं की नौकरी रोजगार और महिला उद्यमी उद्यमिता की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। इस वजह से उन्हें अपने करियर में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद उन्हें सामान्य अवसर नहीं मिल पाते हैं।

इन मानदंडों पर किया गया अध्ययन

- महिलाओं की स्थिति जानने के लिए जिन मानदंडों पर विश्लेषण किया गया उसमें, उनके जाने के स्थान, नौकरी शुरू करना, भुगतान मिलना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, व्यवसाय चलाना, संपत्ति प्रबंधन और पेंशन प्राप्त करना शामिल है।
- अध्ययन के दौरान ज्यादातर महिलाओं ने कुछ सवालों पर चुप्पी साध ली, जैसे- क्या उन्हें पुरुषों की तरह घर से बाहर आने-जाने अथवा यात्रा करने की आजादी है? और क्या उनके यहां का कानून वास्तव में घरेलू हिंसा से उनकी रक्षा करता है?
- जब बात महिला अधिकारों की बात होती है तो जहन हृदय में विकसित देशों की छवि उभरती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि विकसित देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, जो सच नहीं है।
- अमेरिका को इस रिपोर्ट में 83.75 अंक, हासिल हुए हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम को 97.5 फीसद, जर्मनी को 91.88 और ऑस्ट्रेलिया को 96.88 अंक प्राप्त हुए हैं। अमेरिका लैंगिंग समानता वाले टॉप 50 देशों में भी शामिल नहीं है।

मिडिल ईस्ट में सबसे खराब स्थिति

1. अध्ययन में बताया गया है कि महिला अधिकारों की सबसे खराब स्थिति मिडिल ईस्ट में है। रिपोर्ट में सऊदी अरब को सबसे कम 25.63 अंक प्राप्त हुए हैं और वह अंतिम पायदान पर है।
2. इसके अलावा सुडान, यूएई (संयुक्त अरब अमीरात), सीरिया, कतर और ईरान को भी अध्ययन में 35 से कम अंक प्राप्त हुए हैं।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और सब-सहारा अफ्रीका में महिला अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता और सुधार देखने को मिला है।
4. पिछले एक दशक में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की दिशा में सबसे ज्यादा सुधार कांगो देश में हुआ है। एक दशक पहले इस अध्ययन में कांगों को मात्र 42.50 अंक प्राप्त हुए थे, जो मौजूदा अध्ययन में बढ़कर 70 अंक हो गए हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान फिसड्डी डूबी

1. विश्व बैंक द्वारा लैगिंग समानता का ये अध्ययन भारत समेत 187 देशों में किया गया है। इनमें से कई देश समान अंक पाने की वजह से एक ही पायदान पर हैं।
2. इस तरह से अध्ययन में 75 पायदान सबसे नीचे है। बात अगर भारतीय उपमहाद्वीप की करें तो यहां पाकिस्तान की स्थिति सबसे खराब है। मात्र 46.25 अंक के साथ भारत 63वें पायदान पर है।
3. भारतीय उपमहाद्वीप में 73.75 अंकों के साथ मालदीव सबसे ऊपर (वैश्विक स्तर पर 33वें पायदान पर) और भारत 71.25 अंक के साथ दूसरे नंबर पर (वैश्विक स्तर पर 37वें पायदान पर) कायम बिज है।
4. पाकिस्तान, सबसे खराब रहे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के सब-सहारा रीजन के औसत से भी पीछे है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 मार्च 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के नतीजे जारी किए। इनमें मध्य प्रदेश के शहरों ने बाजी मारी है। इंदौर जहां लगातार तीसरी बार सबसे साफ शहर बना है वहीं, उज्जैन और भोपाल भी अपनी-अपनी कैटिगरी में आगे रहे। राज्यों के मामले में छत्तीसगढ़ आगे रहा और सबसे साफ राज्य घोषित किया गया। सर्वेक्षण में इंदौर को सबसे साफ शहर पाया गया है। वहीं, उज्जैन सबसे साफ मध्यम शहर (3-10 लाख आबादी) और भोपाल सबसे साफ राजधानी बना है। वहीं अहमदाबाद सबसे साफ बड़ा शहर (10 लाख से ज्यादा आबादी वाला) बना है और सबसे साफ छोटे शहर (1-3 लाख आबादी) का खिताब NDMC (नई दिल्ली महानगर पालिका) को मिला है।

क्या है

1. दिल्ली कैंट को इसके अलावा सबसे साफ कैंट का दर्जा भी मिला है। उत्तराखंड के गोचर को सबसे साफ गंगा शहर पाया गया है।
2. राज्यों की लिस्ट में टॉप पर जहां छत्तीसगढ़ है, वहीं झारखंड दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है।
3. स्वच्छ सर्वेक्षण 28 दिन में 4,237 शहरों में पेपरलेस और डिजिटल फॉर्मेट में किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सूरी ने बताया कि शहरों ने सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपने नए तरीके अपनाने हैं।
4. 370 से ज्यादा शहर अपने 80% बॉर्डर्स में वेस्ट सेग्रिगेशन करते हैं और अनौपचारिक कूड़ा बीनने वाले 84,000 लोगों को रोजगार मिला है।
5. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए कुंभ मेले की तारीफ की और कहा कि लगभग 1,20,000 शौचालयों की व्यवस्था के साथ-साथ, कूड़ा-कचरा लगातार साफ करने के लिए जो कार्य वहाँ किया गया है, उसे अनेक देशों में सराहा जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयाग-कुंभ से सीख लेकर, बड़े समारोहों के आयोजक स्वच्छता पर अधिक ध्यान देंगे।

पद्मा लक्ष्मी बनीं यूएनडीपी की नई गुडविल एंबेसडर

भारतीय अमेरिकी टेलिविजन हस्ती और फूड एक्सपर्ट पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नई 'गुडविल एंबेसडर' नियुक्त किया गया है और वह विश्वभर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई का समर्थन करेंगी। यूएनडीपी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च 2019 को लक्ष्मी को नियुक्त किए जाने की घोषणा की। एमी पुरस्कार के लिए नामित टेलिविजन हस्ती और पुरस्कार विजेता लेखिका लक्ष्मी अपनी नई भूमिका में असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वंचितों को सशक्त बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करेंगी।

क्या है

1. यूएनडीपी प्रशासक अचिम स्टीनर ने 'गुडविल एंबेसडर' के तौर पर लक्ष्मी के नाम की घोषणा की। लक्ष्मी ने यूएनडीपी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं... तो इस समय हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि महिलाओं और लड़कियों को विश्वभर में सर्वाधिक भेदभाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है'।
2. उन्होंने कहा कि यूएनडीपी गुडविल एंबेसडर के तौर पर वह इस बात पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगी कि असमानता अमीर और गरीब देशों को समान रूप से प्रभावित करती है। लक्ष्मी ने कहा, कई देश गरीबी कम करने में कामयाब रहे हैं लेकिन असमानता की खाई अधिक हठी प्रतीत होती है'।
3. उन्होंने कहा, लिंग, आयु, जाति और नस्ल के आधार पर लिंग असमानता की जाती है। यह खासकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और उन अन्य लोगों को प्रभावित करती है जिन्हें समाज में अकल्पनीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 'स्टीनर ने कहा कि लक्ष्मी पहले भी भेदभाव के खिलाफ और वंचित तबके के लिए आवाज उठाती रही हैं'।
4. उन्होंने कहा, 'आवश्यकता है कि उनकी तरह और लोग भी आवाज उठाएं ताकि हम सतत विकास लक्ष्यों के अपने सपने को साकार कर सकें जो कि लोगों और दुनिया में शांति और समृद्धि का साझा उद्देश्य खाका हैं'।

'पॉलिटिशियन ऑफ द इयर' चुने गए सादिक खान

राजनीतिक जीवन में निरंतर योगदान के लिए लंदन के मेयर सादिक खान को ब्रिटेन का 'पॉलिटिशियन ऑफ द इयर' नामित किया गया। 48 वर्षीय खान के दादा-दादी भारत के रहने वाले थे। उनके माता-पिता पाकिस्तान से ब्रिटेन चले गए थे। उन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में आयोजित एक समारोह में 'पॉलिटिशियन ऑफ द इयर' नामित किया गया।

क्या है

1. ब्रिटेन के साप्ताहिक समाचार पत्र 'एशियन वॉइस' द्वारा वहां आयोजित वार्षिक 'पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवॉर्ड्स' में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री गेविन विलियमसन को 'कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इयर' और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ प्रीति पटेल को 'कंजर्वेटिव पार्टी एमपी ऑफ द इयर' नामित किया गया।
2. चुने जाने पर विलियमसन ने कहा, 'हमारे सशस्त्र बलों को हर एक समुदाय और पृष्ठभूमि के लोग मजबूत बनाते हैं। जो हमें सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं'।
3. वहीं ब्रिटेन की पूर्व कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा, 'मैं जन सेवक के रूप में अपना कार्य जारी रखूंगी'।

एनसीआरबी का स्थापना दिवस

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 11 मार्च 2019 को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा। एनसीआरबी के विभिन्न नन अधिकारियों को ब्यूरो में उनके कार्य की दिशा में उनके लगन एवं समर्पण के लिए श्लाघा प्रमाणपत्र के साथ-साथ एनसीआरबी क्रीडा एवं अन्य स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर एनसीआरबी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी

आयोजन किया जा रहा है जिसमें एनसीआरबी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे। 'नृत्य मंजरी' का एक नृत्य कार्यक्रम अपने प्रदर्शन से अतिथियों का मन लुभाएगा।

क्या है

1. 1986 में गठित एनसीआरबी भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारिता के लिए अधिदेशित है तथा देश के अपराध आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव एवं विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यह जांच अधिकारियों को अद्यतन आईटी टूल्स एवं अपराधों की जांच में सूचना प्रदान करने में सहायक है।
2. एनसीआरबी नीतिगत मामलों एवं अनुसंधान के लिए अपराध, दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं तथा कारागृहों पर आंकड़ों के प्रमाणिक स्रोत के लिए एक नोडल एजेंसी है।
3. ब्यूरो देश में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के प्रत्यायन सहित सभी फिंगर प्रिंस संबंधित मामलों के लिए भी शीर्ष नोडल एजेंसी है। ब्यूरो भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना, अपराध एवं अपराधियों की ट्रेकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन के लिए क्रियान्वयन तथा निगरानी एजेंसी है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस कार्य की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता में वृद्धि के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का सृजन करना है।
4. एनसीआरबी भारतीय पुलिस अधिकारियों एवं विदेश पुलिस अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
5. प्रशिक्षण के दौरान शामिल क्षेत्रों में साइबर अपराध जांच एवं डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस, उन्नत फिंगर प्रिंट विज्ञान, नेटवर्क एवं ई-सुरक्षा, कलर्ड पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम इत्यादि शामिल हैं। हैदराबाद, गांधी नगर, लखनऊ एवं कोलकाता में चार क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (आरसीपीटीसी) भी भारतीय पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए ऐसे ही पाठ्यक्रमों/ठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।

बीएआरसी के नए निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के भौतिकी समूह के विख्यात वैज्ञानिक और निदेशक तथा साह इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के निदेशक डॉ. ए. के. मोहंती ने बीएआरसी के निदेशक का पदभार संभाल लिया। डॉ. मोहंती ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष और सचिव श्री के. एन. व्यास के स्थान पर यह पद संभाला है। डॉ. मोहंती ने बीएआरसी प्रशिक्षण स्कूल के 26वें बैच से स्नातक किया और 1983 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के परमाणु भौतिकी डिवीजन में शामिल हो गए। पिछले 36 वर्षों के दौरान डॉ. मोहंती ने

फ्लैशबैक

1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र केन्द्र केन्द्र मुम्बई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के अन्तर्गत नाभिकीय नाभिकीय किय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबन्धित क्षेत्रों का बहु-विषयी नाभिकीय नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र है।
2. भारत का परमाणु कार्यक्रम डाक्टर डा. डब्लू होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। ३ जनवरी सन् १९५३ को परमाणु उर्जा आयोग के द्वारा परमाणु उर्जा संस्थान (एईईटी) के नाम से आरम्भ हुआ और तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २० जनवरी सन् १९५७ को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
3. इसके बाद परमाणु उर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर १२ जनवरी सन् १९६७ को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र केन्द्र किया गया, जो कि २४ जनवरी सन् १९६६ में डॉ. भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के लिये एक विनम्र श्रद्धांजलि थी।

परमाणु भौतिकी के अनेक क्षेत्रों में कार्य किया।

क्या है

1. डॉ. डाक्टर मोहंती को 1988 में भारतीय भौतिकी सोसायटी का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 1991 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा युवा भौतिक शास्त्री पुरस्कार और 2001 में होमी भाभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परमाणु ऊर्जा विभाग से पुरस्कार मिल चुका है।
2. बीएआरसी के निदेशक का पद भार संभालते हुए, डॉ. मोहंती ने भौतिकी समूह में अपने पूर्व अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जिन्होंने परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में निम्न और उच्च ऊर्जा की बारीकियों को समझाने में मदद की।
3. उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के प्रयासों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को पूरा करने में मदद की जिनमें उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक महत्व के क्षेत्र में वे बीएआरसी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।